प्रदेश सरकार युवाओं को दे रही रोजगार के पर्याप्त अवसर : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को उनके निवास पर वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित किया। बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

- बजट 2025-26 की समीक्षा बैठक में बोले मुख्यमंत्री, "प्रत्येक बजटीय घोषणा को पूरा करने के लिए अधिकारी बनाएं टाइमलाइन"
- 'वन कार्मिक, पटवारी, स्कूल शिक्षक तथा कांस्टेबल के पदों पर भर्ती शीघ्र'

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बजट की प्रत्येक घोषणा को पूरा करने के लिए अधिकारी टाइमलाइन बनाते हुए काम करें। अधिकारी उसी तय सीमा में काम को पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 2047 तक विकसित राजस्थान के संकल्प को ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्येक बजट में राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए विभिन्न प्रावधान किए हैं। हम प्रदेश के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर देते हुए उन्हें आत्मनिर्भर, सशक्त एवं खुशहाल बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न घोषणाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बजटीय घोषणाओं की प्रगति का नियमित फॉलोअप सुनिश्चित कर रही है, जिससे जमीनी स्तर पर इन योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि राज्य के युवाओं को रोजगार मिले। इस दिशा में लगभग 1 लाख 88 हजार सरकारी पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में जनकल्याणकारी योजनाओं की सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण पहुंच सुनिश्चित कर रही है। इसी क्रम में शीघ्र ही वन विभाग में विभिन्न कार्मिकों, पटवारी, स्कूल शिक्षक तथा कांस्टेबल के पदों पर भर्ती की जाएगी। कार्मिक विभाग द्वारा इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। शर्मा ने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालयों सहित सभी चिकित्सा संस्थानों में बेहतर प्रशासनिक प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए हॉस्पिटल मैनेजर का पद सृजित किया जाएगा। विभाग में कार्यरतमुख्य संचालकएवं नर्सिंग स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए जिससे उनकी प्रबंधन दक्षताओं में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि मा योजना तथा आरजीएचएस पोर्टल को इंटीग्रेटेड हैल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत इंटीग्रेट किया जाए। साथ ही, स्वास्थ्य शिविर लगाकर ई-हैल्थ रिकॉर्ड के कार्य में गति लाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अन्न को राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल किया जाए जिससे इसके उपयोग को प्रोत्साहन मिले। उन्होंने कहा कि श्री अन्न की पोषण क्षमता एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए मिड-डे मील तथा मां बाडी केन्द्रों पर पायलट बेसिस पर श्री अन्न आधारित उत्पाद शुरू किए जाएं जिससे बच्चों में सुपोषण तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी आयोजनों में स्वयं सहायता समूह तथा राजीविका की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को उपयोग में लाया जाए जिससे न केवल उन उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि उनकी आय में वृद्धि भी होगी। शर्मा ने अधिकारियों को श्री अन्न के मार्केटिंग, उत्पादन तथा प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समिति बनाने के भी निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि बजटीय घोषणाओं की स्पष्ट कार्ययोजना बनाई जाए जिससे तय समयसीमा में घोषणाएं धरातल पर उतर सकें। उन्होंने कहा कि विभाग अपनी बजटीय घोषणाओं की प्रगति रिपोर्ट तैयार कर उनकी नियमित समीक्षा करें। साथ ही, जिन विभागों में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है उनके कार्य में तेजी लाई जाए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के साथ सर्विस सेक्टर में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी लाई जाएगी। साथ ही, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लाकर राज्य में ट्रेडिंग सेक्टर का विकास एवं संवर्धन किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने सर्कुलर इकोनॉमी के व्यापक प्रसार, ई-बस सेवा, प्रस्तावित एमनेस्टी स्कीम, राजस्थान व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, घरेलू उपभोक्ताओं को पाइप्ड गैस सप्लाई से जोड़ने की प्रक्रिया को गति देने सहित विभिन्न बजटीय घोषणाओं की प्रगति पर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जल संसाधन, उद्योग, नगरीय विकास, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, नागरिक उड्डयन, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, वन, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, राजस्व, स्वायत्त शासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कार्मिक, स्कूल शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण विभाग जैसे प्रमुख विभागों की बजटीय घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

पत्रकारिता में अन्वेषण मूल्यों का अधिकाधिक समावेश हो : बागड़े

विश्व संवाद केन्द्र फाउण्डेशन की ओर से आयोजित नारद जयंती व पत्रकार सम्मान समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने संबोधित किया।

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा है कि पत्रकारिता में खोज और अन्वेषण मूल्यों का विकास जरूरी है। उन्होंने इज़राइल के अपने यात्रा संस्मरण सुनाते हुए कहा कि वहां पत्रकारिता में शोध को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया जाता है। पत्रकारिता में यह दृष्टि अपनाई जाए। उन्होंने भारतीय शोध का अधिकाधिक पेटेंट करवाने का भी आव्हान किया।

राज्यपाल मंगलवार को विश्व संवाद केन्द्र फाउंडेशन द्वारा आयोजित नारद जयंती व पत्रकार सम्मान समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौखिक मीडिया की प्रासंगिकता कई बार दूसरे मीडिया से अधिक होती है। महर्षि नारद इसी मीडिया से जुड़े थे। उन्होंने पीओके के इतिहास की चर्चा करते हुए कहा कि यह उस समय की ऐतिहासिक भूल थी। उन्होंने कहा कि पीओके निर्माण का पाप लार्ड माउंटेन बेटेन का था।

उन्होंने कहा कि भारत में बाहरी आक्रांता इसलिए हावी रहे कि हमारे यहां आंतरिक एकता का अभाव था। एक राजा दूसरे राजा की मदद नहीं करता था। उन्होंने कहा कि भारत बदल रहा है। उन्होंने राष्ट्र भक्ति, सावरकर और भारत पाकिस्तान सम्बन्धों की चर्चा करते हुए कहा कि देश प्रेम का जज्बा बदले भारत की सुनहरी तस्वीर है।

राज्यपाल ने महर्षि अरविंद की चर्चा करते हुए कहा कि पंडित नेहरू ने उनके दर्शन की विशेष रूप से "डिस्कवरी ऑफ इंडिया" में चर्चा की है। अरविंद ने बच्चों की बौद्धिक क्षमता कैसे बढ़ें, इसी पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि लार्ड मैकाले द्वारा भारत को मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखने के लिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति इसी आलोक में लागू की है कि बच्चे भारतीय ज्ञान की परंपरा से जुड़े और उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास हो।

राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति का परिणाम अभी नहीं आयेगा, दस बीस सालों में दिखेगा। आने वाले समय में देश की बौद्धिक और नैतिक प्रगति होगी। उन्होंने कहा कि याद रखें जो देश अपना इतिहास भूलते हैं, वे राष्ट्र का भूगोल भी भूलने लगते हैं।

उन्होंने कहा कि 1150 में भास्कराचार्य ने लीलावती नाम का ग्रन्थ लिखकर बता दिया था कि गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी और आकाश में परस्पर आकर्षण रहता है। इसी शोध को न्यूटन के नाम से हम जानते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पर विश्वास के लिए अपने आत्म में झांकना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि नारद जयंती पत्रकारिता के मूल्यों से जुड़ी है। नारद जी तीनों लोकों में हर प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान मौखिक करते थे। यही तब की पत्रकारिता थी। इससे पहले उन्होंने विभिन्न वर्गों में पत्रकारिता में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि जो पत्रकार सम्मानित हुए हैं, वे समाज के लिए अनुकरणीय हैं।

इससे पहले मुख्य वक्ता पाञ्चजन्य के संपादक हितेश शंकर ने कहा ऑपरेशन सिंदूर में भारत की नैतिकता की विजय हुई। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध भारत की बहुत कुशल और प्रभावी रणनीति की विश्वभर में सराहना हुई है। उन्होंने इस दौरान भारत और पाकिस्तान मीडिया में पत्रकारिता की रही दृष्टि की भी विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर डा. हेमंत सेठिया, चैन सिंह राजपुरोहित ने भी विचार रखे।

सुबोध शिक्षा समिति मामले में दूसरी बार पेश एफआर अस्वीकार

जयपुर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने सुबोध शिक्षा समिति से जुडे एसीबी केस में दूसरी बार पेश एफआर को अस्वीकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में परिवादी की ओर से उठाए बिंदुओं को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। पीठासीन अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने यह आदेश परिवादी लक्ष्मीकांत की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर दिए।

मामले के अनुसार भवानी सहाय, पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रारंभिक जांच कर सत्यापन रिपोर्ट पेश की थी। जिसमें कहा गया कि सुबोध शिक्षा समिति के अध्यक्ष नवरतन कोठारी, प्रोफेसर अश्वनी कुमार, एनके लोहिया और प्राचार्य केबी शर्मा ने मिलीभगत कर पदीय कर्तव्यों का दुरुपयोग किया।

इन्होंने चयन समिति के मिनिट्स में कांट छांट कर केबी शर्मा को एसएस सुबोध पीजी कॉलेज के प्राचार्य पद पर नियम विरुद्ध चयनित किया। उस समय केबी शर्मा भौतिक शास्त्र के व्याख्याता पद पर कार्यरत थे। प्राचार्य पद पर चयनित होने के बाद भी भौतिक शास्त्र के व्याख्याता पद का वेतन के रूप में सरकार से 22.64 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त कर आर्थिक हानि पहुंचाई। मामले में 12 अक्टूबर, 2017 को अदालत में तथ्यों की भूल के आधार पर एफआर पेश की गई। जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर अग्रिम जांच के आदेश दिए। वहीं अब फिर से एसीबी ने एफआर पेश कर दी। परिवादी की ओर से इस एफआर का विरोध करते हुए कहा गया कि एसीबी ने कई बिंदुओं पर जांच नहीं की है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एसीबी को जांच के आदेश दिए हैं।

'आचार्यकुलम् में हाईस्कूल व इंटरमीडिएट का परीक्षाफल शत प्रतिशत रहा'

जयपुर। स्वामी महाराज व आचार्यश्री महाराज द्वारा स्थापित आवासीय विद्यालय आचार्यकुलम् में आज हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट का परीक्षाफल शत प्रतिशत आने पर हर्षोल्लास का वातावरण रहा। इस वर्ष हाईस्कूल में अथर्व ने 99.40 प्रतिशत अंकों के साथ प्रथम, ध्रुव ने 98 प्रतिशत अंकों के साथ द्वितीय, सान्या सेजल ने 97.80 प्रतिशत अंकों के साथ विद्यालय में तृतीय स्थान प्राप्त किया। जबकि 97.60 अंकों के साथ सहज चतुर्थ व 97.40 अंको के साथ अंशुमान व कन्हैया कुमार पंचम स्थान पर रहे। कुल मिलाकर सभी 153 विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने के साथ ही विद्यालय का औसत 86.30 रहा। 21 विद्यार्थियों ने सभी पाँचों विषयों में-1 ग्रेड प्राप्त किए जबकि 43 विदयार्थियों ने विविध विषयों में शतांक अर्जित किए। 95 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 25 रही।

इस वर्ष इण्टरमीडिएट के विज्ञान, मानविकी व वाणिज्यवर्ग में प्राप्तांकों का औसत क्रमशः 83.59, 90.64 व 90.85 रहा जबकि क्रमशः सिद्धेश (99), आर्यमन (98.6) तथा रिद्धिमा (98) ने वर्गवार सर्वोत्तम प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर सभी 97 विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने के साथ ही विद्यालय का औसत 88.38 रहा। सिद्धेश ने 99 प्रतिशत अंकों के साथ विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। 14 विद्यार्थियों ने सभी पाँचों विषयों में -1 ग्रेड प्राप्त किए जबकि 32 विदयार्थियों ने विविध विषयों में शतांक अर्जित किए।

आचार्यकुलम् प्रबंध समिति की उपाध्यक्षा डॉ.ऋतंभरा शास्त्री बहन सहित प्राचार्या स्वाति मुंशी ने उक्त सुअवसर पर विद्यार्थियों समेत सभी आचार्यों व कर्मचारियों को शुभकामनाएँ देते हुए अपने आशीर्वचन प्रदान किए। इस पावन अवसर पर स्वामी अर्जुनदेव, उपप्राचार्य तापस कुमार बेरा, समन्वयिका दीपाजी व मुख्य छात्रावास अधीक्षक व क्रीड़ाध्यक्ष अमित सहित सभी आचार्यवृंद, कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित रहे।

सचिवालय कैंटीन का टेंडर देने पर अंतरिम रोक

जयपुर। हाईकोर्ट ने सचिवालय कर्मचारी संघ के जरिए संचालित सचिवालय कैंटीन का बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए नई फर्म को देने वाले टेंडर पर आगामी सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। वहीं मामले में मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव व उप सचिव से 30 मई तक जवाब देने के लिए कहा है।

भाजपा प्रदेशभर में निकालेगी तिरंगा यात्रा : अरूण चतुर्वेदी

तिरंगा यात्रा को लेकर मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय पर बैठक आयोजित की गई।

- 'जयपुर में 15 मई को अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपड़ तक निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा'

जयपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा की ओर से पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों की कमर तोड़ने का काम किया है। ऐसे में भारतीय सेना के मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से भाजपा की ओर से तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय किया है। तिरंगा यात्रा किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, यह देश का, समाज का हमारी सेना के लिए निकाला जा रहा कार्यक्रम है। इसमें आमजन की भागीदारी रहेगी। तिरंगा यात्रा संभाग स्तर के साथ जिला और फिर विधानसभा क्षेत्रवार भी निकाली जाएगी। तिरंगा यात्रा को लेकर मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय पर बैठक आयोजित की गई।

चतुर्वेदी ने बताया कि बैठक में राजधानी जयपुर में 15 मई को तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया गया है। जयपुर में गुरुवार को सुबह 11 बजे अल्बर्ट हॉल से तिरंगा यात्रा को शुरू किया जाएगा। यात्रा न्यू गेट, बापू बाजार, सांगानेरी गेट होते हुए बड़ी चौपड़ तक जाएगी। तिरंगा यात्रा का बड़ी चौपड़ पर समापन किया जाएगा। तिरंगा यात्रा को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार प्रदेश स्तरी और संभाग स्तरीय कमेटी बनाई गई है। भाजपा प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी और युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अंकित चेची को समिति का प्रदेश समन्वयक बनाया गया है।

भाजपा प्रदेश मंत्री एवं तिरंगा यात्रा कार्यक्रम के प्रदेश समन्वयक भूपेंद्र सैनी ने बताया कि जयपुर के बाद तिरंगा यात्रा प्रदेशभर में निकाली जाएगी। इसके लिए संभाग अनुसार समन्वयक बनाए गए है। इसमे जयपुर में रामलाल शर्मा, विमल अग्रवाल, रघुनाथ नरेडी, प्रेम सिंह बनवासा, उदयपुर संभाग में पिंकेश पोरवाल, दिप्ती माहेश्वरी, पंकज बोराणा, जोधपुर में महेंद्र कुमातव, राजेंद्र बोराणा, नारायण पुरोहित, भरतपुर संभाग में भानुप्रताप सिंह, डीडी कुमावत, भगवान दास शर्मा, बीकानेर संभाग में विजेंद्र पूनिया, विजय आचार्य, महेश व्यास, कोटा संभाग में अनुसूईया गोस्वामी, हेमंत विजयवर्गीय, नरेंद्र नागर और अजमेर में मोतीलाल मीणा, पुखराज पहाडिया और नीरज जैन को संभाग समन्वयक बनाया गया है।

सरकारी स्कूलों में कला शिक्षकों की भर्ती की क्या योजना है : हाईकोर्ट

जयपुर। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आखिरी अवसर देते हुए पूछा है कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में कला शिक्षकों के पदों के सृजन और उन पर भर्तियों होने के संबंध में उनकी क्या कार्य योजना है। वहीं अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि वह आगामी सुनवाई पर उनके निर्देशों की पालना करना सुनिश्चित करे। सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश विमल शर्मा की जनहित याचिका पर दिए। खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उन्हें चित्रकला व संगीत कला से वंचित नहीं किया जा सकता, वह भी तब जबकि आरटीई कानून बन चुका है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से आदेश की पालना के लिए समय दिए जाने का आग्रह किया। इस पर अदालत ने कहा कि पांच महीने से ज्यादा समय हो गया है और राज्य सरकार का प्लान आ जाना चाहिए था। ऐसे में अब राज्य सरकार को अदालत के आदेश की पालना के लिए अंतिम मौका दिया जा रहा है। पिछली सुनवाई पर भी अदालत ने कहा था कि जब कला विषय अनिवार्य विषय है तो स्कूलों में कला शिक्षकों की नियुक्ति होनी ही चाहिए। जनहित याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत हर स्कूल में चित्रकला और संगीत कला के विषय को अनिवार्य किया गया है। इसके बावजूद प्रदेश की करीब 70 हजार स्कूलों में कला शिक्षा देने के लिए कोई विशेषज्ञ शिक्षक नियुक्त नहीं किया गया है। स्कूलों में कला विषय पढाने का काम दूसरे विषयों के शिक्षकों को सौंप दिया जाता है। यह शिक्षा सेवा नियम और एनसीटीई के मानकों के भी खिलाफ है। याचिका में कहा गया कि कला शिक्षा बच्चों के रचनात्मक और मानसिक विकास के लिए जरूरी है। योग्य कला शिक्षकों के अभाव में बच्चों के रचनात्मक विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है और इसके अभाव में उनमें मानसिक तनाव और हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ रही है। याचिका में यह भी बताया गया कि आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार कला अनिवार्य विषय होने के बावजूद इसके लिए न तो कोई पद सृजित किया गया और ना ही कला शिक्षक के रूप में नियुक्ति का प्रावधान है।

पतंजलि संस्थान ने आई.सी.ए.आर. को भेंट की मृदा परीक्षण की ऑटोमेटेड मशीन

पतंजलि संस्थान द्वारा आचार्य बालकृष्ण के मार्गदर्शन में केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान को मृदा परीक्षण की ऑटोमेटेड मशीन 'धरती का डॉक्टर' उपहार स्वरूप भेंट की गई।

हरिद्वार। पतंजलि संस्थान द्वारा आचार्य बालकृष्ण के मार्गदर्शन में केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान को मृदा परीक्षण की ऑटोमेटेड मशीन 'धरती का डॉक्टर' उपहार स्वरूप भेंट की गई। इस मशीन के प्रयोग से न केवल किसानों को अपनी कृषि भूमि की मिट्टी की जांच करने में सहायता मिलेगी,अपितु साथ ही जैविक एवं रासायनिक खेती हेतु आवश्यक उर्वरक प्रयोग के लिए सुझाव भी प्राप्त किए जा सकेंगे।

इस अवसर पर भरूआ एग्री साइंस के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि मृदा परीक्षण मशीन 'धरती का डॉक्टर' को पहले ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रमाणन-पत्र प्रदान किया जा चुका है। इस मशीन के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य के12आवश्यक मानकों का परीक्षण किया जाता है जिसमें मुख्य पोषक तत्व उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश एवं गौण पोषक तत्व बोरॉन, आयरन, जिंक, कॉपर एवं मैंगनीज सम्मिलित हैं। इस मशीन को भारत सरकार द्वारा पेटेंट तथा-सर्टिफिकेट प्राप्त है। उन्होंने बताया कि इस मशीन को पतंजलि के वैज्ञानिकों द्वारा वर्षों के व्यापक शोध के बाद विकसित किया गया है जो किसानों के लिए वरदान है। आचार्य जी ने बताया कि इस मशीन के द्वारा सरल विधियों से फसलानुसार उर्वक संस्तुतियाँ रासायनिक,जैविक एवं मिश्रित तीनों प्रकार से प्राप्त की जा सकती हैं।

कार्यक्रम में केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. राजेंद्र कुमार यादव ने कहा कि धरती का डॉक्टर देश के किसानों तथा भारत सरकार की मृदा स्वास्थ्य योजना के लिए बड़ी उपयोगी मशीन साबित होगी। उन्होंने कहा कि हमारा स्वास्थ्य धरती के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा है। मृदा स्वास्थ्य के लिए12पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर मिट्टी की गुणवत्ता निर्धारित की जाती है। हमारी टीम ने इस मशीन पर गहन परीक्षण किया जिसमें पाया गया कि यह देश की ऐसी पहली मशीन है जिसके द्वारा सभी12पैरामीटर्स की सटीक जाँच की जा सकती है।

इस अवसर पर पतंजलि संस्थान के डॉ. अशोक मेहता ने उपस्थित सभीवैज्ञानिकों का ध्यान पतंजलि संस्थान के द्वारा किसानों के लिए किये जाने वाले निरन्तर प्रयासों की तरफ आकर्षित किया।

माह में चार दिन ग्राम पंचायतों में रात्रि विश्राम करे अधिकारी : दिलावर

जयपुर। शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को शिक्षा विभाग के अंतर्गत संस्कृत विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में गत वर्ष अक्टूबर माह में आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों की प्रगति की समीक्षा की गई। शिक्षामंत्री ने सभी अधिकारियों को प्रत्येक माह कम से कम 4 दिन ग्राम पंचायतों में रात्रि विश्राम करने के निर्देश दिए।

शिक्षा मंत्री ने उच्चाधिकारियों को प्रत्येक 15 दिन में फील्ड में जाकर फीडबैक लेने के निर्देश दिए गए। उन्होंने राइजिंग राजस्थान के दौरान हुए शिक्षा विभाग सम्बंधी एमओयू की प्रगति की समीक्षा की और इनकी तत्परता से क्रियान्विति के निर्देश दिए।

शिक्षामंत्री ने संस्कृत शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर देते हुए राजकीय संस्कृत संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार और विद्यार्थियों में संस्कृत के प्रति रुचि जागृत करने के लिए ठोस एवं सार्थक प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजकीय संस्कृत संस्थानों में नामांकन वृद्धि की दिशा में सार्थक प्रयास करने और इसके लिए रूट मैप तैयार करने तथा राजकीय संस्थानों की मान्यता के नियमों में शिथिलता लाने का सुझाव दिया, आधारभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान देते हुए खेल मैदान के विकास, प्रयोगशालाओं में सुविधा सुधार , भवन में स्वच्छता व बालक और बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय पर विशेष जोर दिया।

शिक्षामंत्री ने विभाग के लंबित मामलों पर भी विस्तार से चर्चा कर सभी तरह की शिकायतों का 10 दिन के भीतर निस्तारण करने के निर्देश दिए।

शिक्षामंत्री ने पर्यावरण सुरक्षा के तहत विभाग को चार करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य सौंपा है। उन्होंने कहा कि प्रति विद्यार्थी 300 पौधे प्रति माह और कार्मिकों को 15 पौधे प्रतिदिन लगाना अनिवार्य होगा। इस कार्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने और स्थानीय एनजीओ के सहयोग से कार्य को गति देने के निर्देश दिए। इस कार्य की क्रियान्वति के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना सुनिश्चित किया गया है।